(b) what are the grades of Indian coal in which sampling is done at present;

(c) whether it is possible to blend different grades of coal to produce standard coal for different industrial purposes including the steel industry; and

(d) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI VASANT SATHE): (a) and (b) For determining the Grade of coal, initially 5 samples from the face of coal seam are drawn. This is followed by taking loading samples as per specification. In case joint sampling with consumers is agreed then the same is done by mutually agreed procedure or Indian Standard Institute method at colliery end or at receiving end. Different grades intt which Indian coals are classified are—

(i) Grades 'A' to 'G' for non-coking coals based on their useful Heat value;

(ii) Gr. SC-I and SC-II for 'Semi-coking coal based on ash-moisture content;

(iii) Gr. ST-I and ST-II and Washery I to Washery IV for coking coal based on ash percentage.

(c) and (d) Blending of low grade coking coal with high grade coking coal is done by steel plants. At present, Coal India Ltd. has no proposal to blend different grades of coal for supply to consumers.

नकली सीमेन्ट का विनिर्माण और बिक्री

2258. **श्रीमती वीणा वर्मा :**
श्री कपिल वर्मा :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में नकली सीमेंट बनाकर बेचने का धंधा जोरों पर चल रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामलों का पता चला है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम अरुणाचलम्) : (क) और (ख) देश में बड़ी मात्रा में नकली सीमेंट के निर्माण तथा विक्रय के संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं है। फिर भी, उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गुणवत्तापूर्ण सीमेंट के निर्माण तथा विक्रय का सुनिश्चिय करने के उद्देश्य से सीमेंट (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 1962 में वर्ष 1983 में संशोधन किया गया था। इस संशोधन के परिणामस्वरूप, 1-7-83 से सीमेंट के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (भूतपूर्व आई एस आई) के मानक चिन्ह को अनिवार्य बना दिया गया है तदनुसार, सीमेंट पर ब्यूरो के मानक चिन्ह के प्रयोग के लिए सभी सीमेंट निर्माताओं के लिए भारतीय मानक ब्यूरो से अनिवार्य रूप से लाइसेंस प्राप्त करना होता है। जो सीमेंट निर्माता भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों को पूरा नहीं करते उनके खिलाफ भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा उचित कार्यवाही की जाती है

Application for setting up Industries in Rajasthan

2259. SHRI SANTOSH BAGRODIA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the number of applications received by Government to set up industries in Rajasthan during the last three years;

(b) the number of letters of Intent and licences issued in this regard during this period; and

(c) the number of applications rejected alongwith the grounds of rejection ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) During the years 1985, 1986 and 1987 (upto 23-11-87), 116, 88 and 70 Industrial Licence applications were received respectively under the provisions of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 for the grant of Letters of

Intent for locating industries in Rajasthan State.

(b) Of these, as on 23-11-1987, 44, 39 and 21 Letters of Intent were issued respectively.

(c) As on 23-11-1987 in respect of Industrial Licence applications received during the years 1985, 1986 and 1987 under the provisions of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 for the grant of Letters of Intent, 71, 47 and 17 rejections/disposals were issued respectively. Various techno-economic factors such as, demand and supply, export potential, availability of raw materials, locational constraints, viability of the scheme and policy considerations are taken into account while approving or rejecting an Industrial Licence application. Grounds of rejection vary from case to case and are duly communicated to the applicants as well as to the State Governments concerned.

भोपाल गैस कांड से पीड़ित लोगों को मुआवजे से संबंधित मामले

2260. श्री शरद यादव : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार के पास कितने लोगों ने भोपाल गैस कांड से पीड़ित लोगों के रूप में पंजीकरण कराया है ;

(ख) क्या उन्हें उनकी चोट के आधार पर श्रेणीबद्ध किया गया है, यदि हां, तो उनकी, श्रेणीवार, संख्या कितनी है ; और

(ग) गैस पीड़ित मृतकों के कितने आश्रितों को मुआवजा दिया गया है और कितने मामलों में अभी निर्णय होना शेष है और इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर०के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार ने गैस से प्रभावित अलग-अलग पीड़ितों द्वारा 31-10-1987 तक दायर किए गए दावों के निम्नलिखित ब्यौरों की सूचना दी है :—

(1) गैस से प्रभावित लोग—525062

(2) पशुओं का नुकसान—414

(3) वाणिज्यिक और व्यापारिक हानि—4698

(4) मृतकों के रिश्तेदारों के दावे—3086

(ग) भोपाल गैस त्रासदी के किसी भी पीड़ित को अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। यूनियन कारबाइड के विरुद्ध मामले में सरकार के पक्ष में निर्णय होने के बाद ही मुआवजे का भुगतान किया जा सकता है। यह मामला चल रहा है और इस पर सक्रिय रूप से कार्यवाही की जा रही है।

Establishing a Refinery Complex near Bhuvanagiri II Well

2261. SHRI M. VINCENT : Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 175 given in the Rajya Sabha on the 9th November, 1987 and state whether Government consider the establishment of a refinery complex in the area utilising the Soviet offer of collaboration in projects which are now in a blue print stage ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI BRAHM DUTT) : There is no proposal at present to set up a new refinery complex to process crude oil from the Cauvery basin.

Contractual Labour in the Bombay Refinery

2262. SHRI PRAMOD MAHAJAN : Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state :

(a) how many labourers have been employed on contract basis in the Hindustan Petroleum's Bombay Refinery.